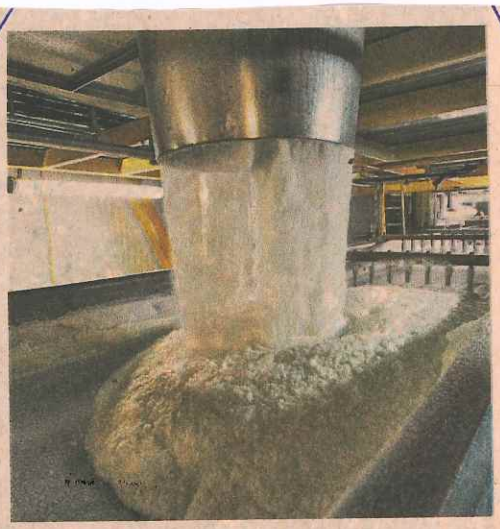

इंडस्ट्री को बंपर शुगर प्रॉडक्शन के अनुमान से टेंशन

[जयश्री भोंसले | पुणे]

केंद्र सरकार दिवाली से पहले चीनी के दाम घटाने की कोशिश कर रही है। उधर, शुगर इंडस्ट्री अगले साल यानी 2018-19 में उत्पादन बढ़ने के अनुमान से टेंशन में है। इस साल देश में चीनी की सप्लाई कम रही, जिससे दाम में मजबूती बनी हुई है।

शुगर प्रॉडक्शन में 23 पर्सेंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। इससे सरकार और ग्राहकों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन शुगर इंडस्ट्री की चिंता बढ़ गई है। अगर दाम कम होते हैं तो अगले साल इंडस्ट्री को सरकार से मदद की अपील करनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में एक सहकारी शुगर मिल के मालिक ने कहा, 'हमें फिर से सरकार के पास भीख मांगने जाना पड़ेगा।' 2016-17 में किसानों को दूसरी फसलों के मुकाबले गन्ने से बढ़िया रिटर्न मिला। गन्ने की खेती वाले इलाकों में जलाशय भर रहे हैं। इसलिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को 2018-19 में गन्ने की बुआई बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 2017-18 में 1 करोड़ टन से ज्यादा चीनी का उत्पादन हो सकता है। 2018-19 में भी इसका प्रॉडक्शन इसी लेवल के करीब रहने के आसार हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सूखा प्रभावित इलाकों में चीनी का उत्पादन भी अगले दो साल में रिकवर करने की उम्मीद है। इंडस्ट्री को डर है कि 2018-19 में अधिक प्रॉडक्शन से चीनी सस्ती हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मिलें किसानों को गन्ने के लिए फेयर एंड रिम्यूनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) नहीं दे पाएंगी। मिलों के लिए किसानों को एफआरपी देना कानूनन अनिवार्य है।

शुगर प्रॉडक्शन में 23 पर्सेंट की बढ़ोतरी का अनुमान है। इससे सरकार और ग्राहकों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन शुगर इंडस्ट्री की चिंता बढ़ गई है

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने सरकार से कहा है कि वह मिलों के योगदान से एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड (पीएसएफ) तैयार करे। इस फंड से शुगर मिलों को ऐसे वक्त में किसानों को एफआरपी चुकाने में मदद मिलेगी, जब चीनी के दाम कम रहेंगे। अगले साल भारत में चीनी का बंपर उत्पादन होने पर क्या यहां से एक्सपोर्ट की इजाजत मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अटकलें लग रही हैं। इंडिया ने 2016-17 में 8 लाख टन रॉ शुगर के इंपोर्ट की मंजूरी दी थी ताकि शुगर की घरेलू मार्केट में कीमतें नियंत्रण में रहें। साथ ही सूखा प्रभावित इलाकों में मौजूद शुगर मिलों को गन्ने की कमी के दौर में भी कामकाजी बने रहने में मदद मिल सके।

Economic Tim.
5/10/17